हिन्दी पाक्षिक

सेमन्या कण्वघाटी

RNI No.: UTTHIN/2013/54659

वर्ष-13 | अंक-18 | हरिद्वार, शनिवार 01 अगस्त, 2026 | मूल्य-दो रूपया मात्र | पृष्ठ-8

श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

हरिद्वार,संवाददाता । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी 30 जुलाई से प्रारंभ होने वाली कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करे कि किसी भी स्तर पर कोई कमी न रहे तथा सभी व्यवस्थाएं पूरी संवेदनशीलता, समन्वय और सेवा-भाव के साथ संचालित हों। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं के स्वागत-सत्कार तथा विभिन्न स्थानों पर भंडारों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग से पर्याप्त संख्या में साफ-सुथरे पिंक टॉयलेट्स स्थापित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था राज्य के सभी प्रमुख स्थलों पर की जाए।मंगलवार को मेला नियंत्रण भवन सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कांवड़ मेले की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तराखण्ड की आस्था, प्रशासनिक क्षमता, सेवा-भाव और कार्यकुशलता का भी प्रतीक है। हमारा लक्ष्य 'सुरक्षित कांवड़, सुव्यवस्थित कांवड़ और स्वच्छ कांवड़' होना चाहिए। प्रत्येक श्रद्धालु देवभूमि उत्तराखण्ड से सुरक्षित, संतुष्ट और सुखद अनुभव के साथ लौटे, यही राज्य सरकार का 'विकल्प रहित संकल्प' है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विभिन्न प्रकार की वैश्विक चुनौतियों के बावजूद तमाम क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उत्तराखण्ड में भी

प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार तीर्थाटन और पर्यटन गतिविधियों में लगातार वृद्धि हो रही है।उन्होंने कहा कि इस वर्ष अब तक चारधाम यात्रा में 45 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि 55 हजार से अधिक श्रद्धालु आदि कैलाश की यात्रा कर चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार तीन गुना अधिक तीर्थयात्री उत्तराखण्ड पहुंचेंगे। इस वर्ष कांवड़ यात्रा में भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसलिए सभी व्यवस्थाएं उसी अनुरूप की जाएं, जिसमें धार्मिक परंपराओं एवं गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापारियों, धर्माचार्यों एवं संत समाज के सहयोग से कांवड़ मेले का सफल संचालन और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि धर्माचार्यों एवं संतों के संदेशों पर आधारित वीडियो संदेश तैयार कर कांवड़ यात्रियों तक पहुंचाए जाएं, ताकि यात्रा अनुशासित एवं मर्यादित ढंग से संपन्न हो सके।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन एवं एआई आधारित निगरानी प्रणाली का प्रभावी उपयोग किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों के विरुद्ध तत्काल एवं कठोर कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने अथवा भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने वालों पर भी कड़ी निगरानी रखते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक प्लान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। कांवड़ यात्रियों एवं स्थानीय नागरिकों के लिए आवश्यकतानुसार पृथक यातायात व्यवस्था बनाई जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानी न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में वीआईपी मूवमेंट के कारण श्रद्धालुओं की यात्रा प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी प्रमुख पड़ावों एवं मेला क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में मेडिकल कैंप, एंबुलेंस, चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध रहे। प्रमुख घाटों पर वाटर एंबुलेंस तैनात किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जल पुलिस तथा अग्निशमन सेवाओं को पूरी तरह अलर्ट रखा जाए। भारी वर्षा, जलभराव अथवा अन्य आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए पूर्व तैयारी एवं त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे कांवड़ मार्ग एवं मेला क्षेत्र में पेयजल, शौचालय, विश्राम स्थलों, प्रकाश व्यवस्था तथा स्वच्छता की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नियमित सफाई अभियान चलाया जाए तथा नो-प्लास्टिक अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि यात्रा समाप्त होने के बाद भी तत्काल सफाई कर क्षेत्र को पूर्व स्थिति में लाया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि होटलों, ढाबों एवं प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाए। सभी प्रतिष्ठानों पर लाइसेंस एवं पंजीकरण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए । किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली घटना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें। चौबीसों घंटे कंट्रोल रूम एवं हेल्पलाइन पूरी तरह सक्रिय रहें। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रतिदिन व्यवस्थाओं की समीक्षा कर किसी भी समस्या का तत्काल समाधान सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने हर की पैड़ी, कांगड़ा पुल एवं अन्य प्रमुख घाटों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल पुलिस की पर्याप्त तैनाती, भीड़ नियंत्रण व्यवस्था एवं आपातकालीन निकासी योजना को पूरी तरह तैयार रखने को कहा। उन्होंने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निरंतर जारी रखने तथा अत्यधिक ऊंची कांवड़ एवं निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि वाले डीजे वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के निर्देश दिए। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस बल एवं हेल्प डेस्क को सक्रिय रखने पर भी विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान आगामी महाकुंभ-2027 की तैयारियों में व्यवधान नहीं आना चाहिए। दोनों व्यवस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय बनाते हुए विकास कार्यों एवं तैयारियों को निर्धारित समय पर आगे बढ़ाया जाए, ताकि उत्तराखण्ड एक बार फिर अपनी उत्कृष्ट व्यवस्थाओं का उदाहरण प्रस्तुत कर सके।

कारगिल के वीरों को नमन, शहीद परिवारों का हुआ सम्मान

हरिद्वार । कारगिल विजय दिवस पर शनिवार को जनपद में शौर्य दिवस हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कलक्ट्रेट परिसर में कारगिल शहीदों और अन्य वीर सैनिकों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिमरनजीत कौर ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिलाधिकारी ने कहा कि कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए देश की रक्षा की। उत्तराखंड के 75 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनका राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि सीमा पर तैनात सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिजनों की समस्याओं का जिला प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर समाधान करेगा। कार्यक्रम में जनपद के आठ शहीद सैनिकों की वीर नारियों और परिजनों को शॉल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही एनसीसी कैडेटों और खेल विभाग छात्रावास के पदक विजेता छात्र-छात्राओं को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। मेयर किरन जैसल ने कहा कि कारगिल के वीर सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान देशवासियों को राष्ट्रभक्ति और समर्पण की प्रेरणा देता रहेगा। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिमरनजीत कौर ने पूर्व सैनिकों, सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए नि:शुल्क विधिक सहायता एवं नालसा की योजनाओं की जानकारी दी। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी एवं विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) डॉ. सरिता पांवर ने कारगिल युद्ध का स्मरण करते हुए जनपद के शहीद राइफलमैन मान सिंह गोसाईं के बलिदान को याद किया। इस अवसर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी अमित कुमार चंद, जिला सूचना अधिकारी रती लाल शाह, सूबेदार सुधीर चंद्र, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वीरेंद्र सिंह रावत, शहीद सैनिकों के परिजन, पूर्व सैनिक, एनसीसी कैडेट, छात्र-छात्राएं तथा विभिन्न सैनिक संगठनों के पदाधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

फिर लौटेगी विलुप्त होती दून बासमती की खुशबू

देहरादून,संवाददाता। देश-विदेश में अपनी विशिष्ट सुगंध, स्वाद और गुणवत्ता के लिए पहचान रखने वाली देहरादून की पारंपरिक दून बासमती की खुशबू एक बार फिर खेतों में लौटने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प, जिला प्रशासन की पहल और किसानों की मेहनत से दून बासमती के पुनर्जीवन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को सफलता मिलने लगी है। वर्ष 2025 में किए गए ट्रायल के सफल परिणाम के बाद इस वर्ष 2.2 दून बासमती की खेती का दायरा बढ़ाकर 75 हेक्टेयर कर दिया गया है। जिले के करीब 160 किसान इसकी रोपाई कर रहे हैं। दून बासमती के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिला प्रशासन, कृषि विभाग और ग्रामोत्थान के समन्वित प्रयासों से न केवल इसकी खेती को दोबारा बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि किसानों को बाजार उपलब्ध कराने, गुणवत्तापूर्ण बीज के संरक्षण, टेस्टिंग और ब्रांडिंग पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

75 हेक्टेयर में 160 किसानों ने शुरू की खेती

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चैहान ने बताया कि देहरादून की पारंपरिक दून बासमती को पुनर्जीवित करने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। प्रारंभिक ट्रायल के दौरान करीब 65 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती कराई गई थी, जिसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए। इसके बाद इस वर्ष दून बासमती की खेती का क्षेत्र बढ़ाकर 75 हेक्टेयर किया गया है। जिले के 160 किसानों ने इस वर्ष इसकी रोपाई शुरू की है।

उन्होंने बताया कि सहसपुर और विकासनगर के बाद रायपुर तथा डोईवाला विकासखंड के किसान भी दून बासमती की खेती के प्रति उत्साह दिखा रहे हैं। किसानों के सहयोग और कृषि विभाग व ग्रामोत्थान के समन्वित प्रयासों से दून बासमती की पुरानी पहचान को पुन: स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि आने वाले समय में दून बासमती को उसकी विशिष्ट सुगंध, गुणवत्ता और स्थानीय पहचान के साथ एक मजबूत ब्रांड के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे किसानों को बेहतर बाजार और अधिक आय का अवसर मिल सके।

गत वर्ष सफल रहा ट्रायल, किसानों से सीधे खरीदी गई फसल

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि वर्ष 2025 में दून बासमती का ट्रायल सफल रहा। पिछले वर्ष करीब 65 हेक्टेयर क्षेत्र में 100 से अधिक किसानों ने इसकी खेती की थी। ट्रायल के उत्साहजनक परिणामों के बाद किसानों का रुझान इस पारंपरिक फसल की ओर बढ़ा है।

उन्होंने बताया कि रीप (ग्रामीण उद्यमिता एवं आजीविका परियोजना) के माध्यम से किसानों से उनकी उपज की सीधे खरीद की गई। पिछले वर्ष जिला प्रशासन की पहल पर 200 क्विंटल से अधिक दून बासमती धान ष्65 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया, जिसके एवज में किसानों के खातों में 13 लाख रुपये से अधिक की धनराशि सीधे हस्तांतरित की गई।

सीडीओ ने कहा कि दून बासमती की खेती को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना भी प्राथमिकता में है। रीप और हिलान्स के माध्यम से दून बासमती की मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

विकासनगर में बनेगा सीड बैंक, टेस्टिंग सुविधा भी होगी

दून बासमती के संरक्षण और किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए विकासनगर में जल्द सीड बैंक स्थापित किया जाएगा। इसके माध्यम से भविष्य में किसानों को बेहतर गुणवत्ता और अच्छी उपज देने वाला दून बासमती का बीज आसानी से उपलब्ध कराया जा सकेगा। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चैहान ने बताया कि विकासनगर में दून बासमती की प्रॉपर टेस्टिंग सुविधा विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दून बासमती की विशिष्ट सुगंध, गुणवत्ता और स्थानीय पहचान को ब्रांड के रूप में विकसित कर किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ देहरादून की पारंपरिक कृषि विरासत को संरक्षित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।

550 हेक्टेयर से सिमटकर 150-200 हेक्टेयर रह गई खेती

मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि दून बासमती को लेकर किसानों में फिर से अच्छा रुझान देखने को मिल रहा

(शेष पृष्ठ 3 पर)

सम्पादकीय

फिर उभरा पहाड़ों का दर्द

हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड की पहचान उसकी प्राकृतिक सुंदरता, ऊंचे-ऊंचे पर्वत, कल-कल बहती नदियां और हरे-भरे जंगलों से है। लेकिन यही पहाड़ हर वर्ष बरसात के मौसम में अपने सबसे भयावह रूप में दिखाई देते हैं। मानसून की पहली तेज बारिश के साथ ही भूस्खलन, सड़क धंसने, पुल बहने, बादल फटने और नदियों के उफान की खबरें आम हो जाती हैं। ऐसा लगता है मानो पहाड़ हर साल अपने जख्मों की कहानी फिर से सुनाने लगते हैं। बरसात का मौसम पहाड़ों के लिए केवल प्राकृतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि एक कठिन परीक्षा है। यह परीक्षा केवल प्रकृति की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की भी है जो इन दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। सड़कें बंद होते ही गांवों का संपर्क टूट जाता है। मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाते, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, किसानों की उपज बाजार तक नहीं पहुंचती और पर्यटकों की आवाजाही रुक जाती है। कई बार तो पूरा गांव कई दिनों तक दुनिया से कट जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि हिमालय विश्व की सबसे युवा पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी चट्टानें अपेक्षाकृत कमजोर हैं और लगातार भूगर्भीय गतिविधियां यहां की संवेदनशीलता बढ़ाती हैं। पहले जहां वर्षा लंबे समय तक संतुलित रूप से होती थी, वहीं अब कुछ घंटों में अत्यधिक बारिश होने लगी है। जलवायु परिवर्तन ने मौसम के मिजाज को पूरी तरह बदल दिया है। कम समय में अत्यधिक वर्षा से मिट्टी का कटाव बढ़ता है और पहाड़ों की ढलानें कमजोर होकर खिसकने लगती हैं। इसके साथ ही अनियोजित विकास ने भी समस्या को गंभीर बनाया है। सड़क चौड़ीकरण, सुरंग निर्माण, पर्वतीय ढलानों की अंधाधुंध कटाई, नदियों के किनारे निर्माण और जंगलों की कमी ने प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित किया है। विकास आवश्यक है, लेकिन यदि वह प्रकृति की क्षमता को नजरअंदाज करके किया जाए तो उसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों के सामने सबसे बड़ी चुनौती विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की है। बेहतर सड़कें, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन विकास जरूरी हैं, लेकिन इनके लिए वैज्ञानिक योजना और पर्यावरणीय मानकों का पालन भी उतना ही आवश्यक है। ढलानों को सुरक्षित बनाए बिना सड़क निर्माण, उचित जल निकासी व्यवस्था के अभाव में निर्माण कार्य और भूगर्भीय अध्ययन की अनदेखी भविष्य के बड़े संकट को जन्म देती है। हर प्राकृतिक आपदा के बाद सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ता है। छोटे दुकानदारों का व्यापार ठप हो जाता है, होटल और होम-स्टे खाली हो जाते हैं, टैक्सी और परिवहन व्यवसाय प्रभावित होता है। खेती योग्य भूमि बह जाती है और पशुपालन पर भी संकट गहरा जाता है। कई परिवारों के लिए बरसात का मौसम रोजी-रोटी की सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। चारधाम यात्रा और पर्यटन भी बरसात के दौरान प्रभावित होते हैं। मार्ग बंद होने से यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है। हर वर्ष आपदा के बाद राहत और पुनर्वास का कार्य शुरू हो जाता है, लेकिन वास्तविक समाधान इससे कहीं आगे है। आवश्यकता है कि संवेदनशील क्षेत्रों की वैज्ञानिक मैपिंग की जाए, आधुनिक मौसम पूर्वानुमान और अर्ली वार्निंग सिस्टम को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, ढलानों का वैज्ञानिक उपचार हो, वर्षाजल निकासी की बेहतर व्यवस्था बनाई जाए और व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाए। स्थानीय समुदायों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देना, पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और पर्यावरण के अनुकूल विकास मॉडल अपनाना भी समय की मांग है। आपदा आने के बाद राहत पहुंचाने से अधिक महत्वपूर्ण है कि ऐसी परिस्थितियां बनने ही न दी जाएं। उत्तराखंड के पहाड़ केवल पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और जीवन का आधार हैं। यदि इन पहाड़ों की संवेदनशीलता को समझे बिना विकास की दौड़ जारी रही तो हर मानसून नई त्रासदी लेकर आएगा। अब समय आ गया है कि अल्पकालिक मरम्मत की जगह दीर्घकालिक और वैज्ञानिक समाधान को प्राथमिकता दी जाए। प्रकृति हमें बार-बार संकेत दे रही है कि विकास और पर्यावरण विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक होने चाहिए।

मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना के अंतिम ट्रायल संपन्न, 652 खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा

हरिद्वार । मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों के चयन के लिए आयोजित तीन दिवसीय अंतिम ट्रायल मंगलवार को योगस्थली खेल परिसर, रोशनाबाद में संपन्न हो गए। ट्रायल में 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 652 बालक-बालिकाओं ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चयनित खिलाड़ियों को योजना के तहत 1,500 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। योजना के तहत बहादराबाद, रुड़की, भगवानपुर, नारसन, लक्सर, खानपुर विकासखंड, नगर निगम हरिद्वार व रुड़की तथा नगर पालिका शिवालिक नगर, लक्सर और मंगलौर क्षेत्र के खिलाड़ियों ने अंतिम ट्रायल में भाग लिया। 26 जुलाई को 8-9 एवं 9-10 वर्ष, 27 जुलाई को 10-11 एवं 11-12 वर्ष तथा 28 जुलाई को 12-13 एवं 13-14 वर्ष आयु वर्ग के ट्रायल आयोजित किए गए?

ट्रायल में 8-9 एवं 9-10 वर्ष आयु वर्ग में 200, 10-11 एवं 11-12 वर्ष आयु वर्ग में 224 तथा 12-13 एवं 13-14 वर्ष आयु वर्ग में 228 बालक-बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। खिलाड़ियों का मूल्यांकन 30 मीटर फ्लाइंग रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, फॉरवर्ड बेंड रीच, 6म10 शटल रन, मेडिसिन बॉल थ्रो, 600 मीटर दौड़ सहित बैटरी टेस्ट और खेल दक्षता के आधार पर किया गया।

मेरिट आधारित चयन: मेरिट के आधार पर प्रत्येक आयु वर्ग से 25 बालक और 25 बालिकाओं का चयन छात्रवृत्ति योजना के लिए किया जाएगा। ट्रायल का संचालन जिला खेल विभाग, जिला शिक्षा विभाग, जिला चिकित्सा विभाग और जिला युवा कल्याण विभाग के संयुक्त समन्वय से किया गया।

न्यूली लिफ्ट सिंचाई योजना से बदली गांवों की तस्वीर, बंजर खेतों में लौटी हरियाली और किसानों के चेहरों पर मुस्कान

-न्यूली लिफ्ट सिंचाई योजना- बंजर खेतों में लौटी हरियाली, किसानों के जीवन में आई खुशहाली

-जब खेतों तक पानी पहुँचता है, तब केवल फसलें ही नहीं, बल्कि किसानों की उम्मीदें भी हरी-भरी हो जाती हैं

-331.43 लाख की योजना बनी किसानों के लिए वरदान, चन्द्रभागा गाड़ से 500 मीटर ऊंचाई तक पहुंचा पानी; खेती, रोजगार और आय को मिला नया आधार

टिहरी। जनपद टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर विकासखंड स्थित न्यूली और सेमी सेमला गांवों में न्यूली लिफ्ट सिंचाई योजना ने ग्रामीण विकास की नई इबारत लिखी है। वर्षों से सिंचाई के अभाव में बंजर पड़े खेत अब लहलहा रहे हैं। चन्द्रभागा गाड़ से करीब 500 मीटर ऊंचाई तक पानी पहुंचाने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने किसानों को न केवल नियमित सिंचाई उपलब्ध कराई है, बल्कि उनकी आय, रोजगार और भविष्य की

उम्मीदों को भी नई दिशा दी है।

सिंचाई के अभाव में बंजर थे खेत, वर्षा पर निर्भर थी खेती

न्यूली और सेमी सेमला गांवों के किसान लंबे समय से सिंचाई सुविधा के अभाव में खेती की कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। अधिकांश कृषि भूमि वर्षभर बंजर पड़ी रहती थी और किसान केवल वर्षा आधारित खेती पर निर्भर थे। कम उत्पादन और सीमित आय के कारण कई परिवारों को रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ता था।

331.43 लाख की योजना ने बदली खेती की तस्वीर

सिंचाई विभाग के लघु डाल खंड, उत्तरकाशी द्वारा नाबार्ड की RIDF-28 योजना के अंतर्गत 331.43 लाख की लागत से न्यूली लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण कराया गया। इस परियोजना के माध्यम से चन्द्रभागा गाड़ से पानी लिफ्ट कर लगभग 500 मीटर ऊंचाई पर स्थित खेतों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे किसानों को वर्षभर सिंचाई की सुविधा मिल रही है।

बंजर भूमि पर फिर लहलहाई फसलें

योजना के शुरू होने के बाद वर्षों से खाली पड़े खेतों में दोबारा खेती शुरू हो गई है। नियमित सिंचाई मिलने से किसानों ने पारंपरिक फसलों के साथ-साथ सब्जियों, औषधीय पौधों और अन्य नकदी फसलों की खेती भी शुरू कर दी है। इससे कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ किसानों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

खेती से बढ़ी आय, युवाओं का बढ़ा रुझान

ग्रामीणों का कहना है कि सिंचाई सुविधा मिलने से खेती अब लाभ का व्यवसाय बनती जा रही है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े हैं और युवा भी आधुनिक कृषि की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे क्षेत्र में पलायन की समस्या कम होने की उम्मीद भी मजबूत हुई है।

ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता का बना मॉडल

न्यूली लिफ्ट सिंचाई योजना केवल सिंचाई सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण विकास, कृषि समृद्धि और आत्मनिर्भरता का सफल मॉडल बनकर उभरी है। यह परियोजना साबित करती है कि यदि किसानों को समय पर पानी जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो वे अपने श्रम और संकल्प से बंजर भूमि को भी समृद्ध कृषि क्षेत्र में बदल सकते हैं।

किसानों ने सरकार का जताया आभार

ग्रामीणों और किसानों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किसानों के हित में संचालित योजनाओं की सराहना करते हुए न्यूली लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि यह योजना क्षेत्र में समृद्धि, आत्मनिर्भरता और खुशहाली का नया अध्याय लिख रही है तथा आने वाले वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करेगी।

नगर पालिका बाड़ाहाट में भाजपा के तीन सभासद नामित, कार्यकर्ताओं में उत्साह

उत्तरकाशी। प्रदेश सरकार ने नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट, उत्तरकाशी में भारतीय जनता पार्टी के तीन कार्यकर्ताओं को नामित सभासद नियुक्त किया है। सरकार के इस निर्णय के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। नामित सभासदों में पूर्व सभासद अरविंद उनियाल, यशपाल सिंह विष्ट (जोश्याड़ा) तथा राजपाल सिंह चौहान (बाड़ाहाट) शामिल हैं।

नामित सभासदों ने मुख्यमंत्री, शहरी विकास विभाग और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे संगठन और सरकार की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए नगर के समग्र विकास के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि नगर की मूलभूत सुविधाओं के विस्तार, जनसमस्याओं के त्वरित समाधान तथा विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को उनकी प्राथमिकता रहेगी। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए इसे संगठन के समर्पित कार्यकर्ताओं का सम्मान बताया। उनका कहना है कि तीनों नामित सभासदों के परिषद से जुड़ने से विकास कार्यों में तेजी आएगी और जनहित से जुड़े मुद्दों के समाधान को मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट में पहले से 11 निर्वाचित सभासद हैं। अब तीन नामित सभासदों के शामिल होने से परिषद में जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ गई है, जिससे विकास योजनाओं के बेहतर संचालन की उम्मीद जताई जा रही है। इस अवसर पर डॉ. चंडी प्रसाद भट्ट (प्रदेश संयोजक, चिकित्सा प्रकोष्ठ), सतीश सेमवाल रावल (गंगोत्री धाम), मंगल सिंह चौहान (वरिष्ठ गौ सेवा प्रमुख) तथा चंदन राणा (देवभूमि जन सेवा प्रमुख) सहित अनेक भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने तीनों नामित सभासदों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

लालढांग छात्रावास में स्वच्छता पखवाड़ा, छात्रों को दिलाई स्वच्छता की शपथ

हरिद्वार । नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास, लालढांग में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के सहयोग से स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया। विद्यार्थियों को स्वच्छता का महत्व बताने के साथ ही स्वच्छता संबंधी सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। वार्डन ने विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास, लालढांग में मंगलवार को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के सहयोग से स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। साथ ही छात्रावास को स्वच्छता संबंधी सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। छात्रावास के वार्डन योगेश्वर कुमार ने कहा कि स्वच्छता स्वस्थ जीवन का आधार है। मन, तन, घर और गांव की स्वच्छता से ही स्वच्छ समाज और स्वच्छ देश का निर्माण संभव है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने आसपास का वातावरण साफ-सुथरा रखने का संकल्प लेने का आह्वान किया।बीपीसीएल के सुरक्षा अधिकारी नितिन मोरे ने विद्यार्थियों को वर्ष में कम से कम 100 घंटे, यानी प्रति सप्ताह दो घंटे श्रमदान करने का संकल्प दिलाया।बिक्री अधिकारी भावेश श्रीवास्तव ने स्वच्छता के सामाजिक और व्यक्तिगत महत्व पर प्रकाश डाला।कार्यक्रम के दौरान बीपीसीएल की ओर से छात्रावास को डस्टबिन, झाड़ू, फिनाइल, हार्पिक, सैनिटाइजर, हैंडवॉश समेत अन्य स्वच्छता सामग्री भेंट की गई। इस अवसर पर बीपीसीएल के दानिश, सूरज, राजकुमार, दीपक तथा छात्रावास के आयुष, आकाश, गोपाल, आशीष, तेजस्वी, प्रमोद, दीपा, मीना, संतोषी सहित अन्य छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

हाईवे, कांवड़ पटरी और आंतरिक मार्गों के काम 20 जुलाई तक पूरे करें

हरिद्वार । कांवड़ मेले की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे प्रशासन ने हाईवे, कांवड़ पटरी और आंतरिक मार्गों के सभी निर्माण कार्य 20 जुलाई तक पूरे करने के निर्देश दिए हैं। डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर 25 जुलाई तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने, गुणवत्ता बनाए रखने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंगलवार को डीएम और एसएसपी ने अधिकारियों के साथ हिल बाईपास, सप्तऋषि क्षेत्र, रोड़ी बेलवाला मैदान और नजीबाबाद हाईवे का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। डीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि हाईवे, कांवड़ पटरी और आंतरिक मार्गों के सभी निर्माण कार्य 20 जुलाई तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। इसके बाद सड़कों पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होगा। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न करने के भी निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान पार्किंग, यातायात प्रबंधन, बैरिकेडिंग, सड़क मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को मेले से जुड़े सभी कार्य 25 जुलाई तक पूरा करने के निर्देश दिए गए।डीएम मयूर दीक्षित ने कहा कि कांवड़ियों की सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस वर्ष कांवड़ मेले और महाकुंभ की तैयारियां साथ-साथ चल रही हैं। ऐसे में कुंभ मेला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाएंगी।एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि चार करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के संभावित आगमन को देखते हुए सुरक्षा और यातायात की व्यापक योजना तैयार की गई है। कांवड़ पटरी मार्ग, हाईवे, पार्किंग स्थलों और प्रमुख चौराहों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। आधुनिक निगरानी प्रणाली के जरिए यातायात संचालन सुचारु रखा जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

(पृष्ठ 1 का शेष)

फिर लौटेगी विलुप्त....

है। रीप के माध्यम से पिछले वर्ष किसानों से दून बासमती की उपज 65 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी गई। उन्होंने बताया कि अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का संरक्षण किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने बताया कि एक समय दून बासमती की खेती करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में होती थी, लेकिन धीरे-धीरे इसका क्षेत्र सिमटकर लगभग 150 से 200 हेक्टेयर रह गया। अब इसे पुनः व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

'प्रशासन और कृषि विभाग कर रहा पूरा सहयोग'

हरबर्टपुर निवासी किसान सूर्य प्रकाश बहुगुणा ने बताया कि दून बासमती की खेती को बढ़ावा देने में जिला प्रशासन, कृषि विभाग और ग्रामोत्थान की ओर से किसानों को पूरा सहयोग मिल रहा है। उनके क्षेत्र के करीब 25 से 30 किसान दून बासमती के पुनर्जीवन अभियान से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयास और जिला प्रशासन की अभिनव पहल से विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी दून बासमती को नया जीवन मिल रहा है। किसानों को उम्मीद है कि आने वाले समय में इसकी खेती का क्षेत्र बढ़ेगा और उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य भी मिलेगा।

बीज से ब्रांडिंग तक: दून बासमती के संरक्षण की समग्र पहल

दून बासमती के पुनर्जीवन के लिए जिला प्रशासन की ओर से खेती के विस्तार से लेकर बीज संरक्षण, वैज्ञानिक टेस्टिंग, किसानों से सीधी खरीद, बेहतर बाजार और ब्रांडिंग तक समग्र स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2025 के सफल ट्रायल और इस वर्ष बढ़े खेती क्षेत्र ने इस पारंपरिक बासमती की वापसी की उम्मीद को मजबूत किया है। प्रशासन और कृषि विभाग का मानना है कि यदि इन प्रयासों को निरंतरता मिली तो आने वाले वर्षों में दून बासमती न केवल देहरादून की पारंपरिक कृषि विरासत के रूप में फिर से स्थापित होगी, बल्कि अपनी विशिष्ट सुगंध और गुणवत्ता के दम पर देशभर में 'दून की बासमती' की नई पहचान भी कायम कर सकेगी।

हरकी पैड़ी पर जिला पॉश समिति ने की गंगा आरती, लिया निष्पक्ष फैसलों का संकल्प

हरिद्वार (संवाददाता)। धार्मिक नगरी के हरकी पैड़ी तट पर एक अनोखी और महत्वपूर्ण शुरुआत देखने को मिली। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए गठित 'हरिद्वार जिला स्तरीय पॉश (POSH) समिति' के पदाधिकारियों ने मां गंगा की पूजा-अर्चना और भव्य आरती कर अपने कर्तव्यों के निष्पक्ष निर्वहन का आशीर्वाद लिया। गंगा सभा के पुरोहितों के सानिध्य में पूरे विधि-विधान से यह अनुष्ठान संपन्न हुआ। समिति की अध्यक्ष और 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान की ब्रांड एंबेसडर डॉ. मनु शिवपुरी ने इस मौके पर कहा कि मां गंगा स्वयं नारी शक्ति का प्रतीक हैं। उनसे निष्पक्ष न्याय करने की शक्ति का आशीर्वाद मांगा गया है। डॉ. शिवपुरी ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया पॉश एक्ट कामकाजी महिलाओं के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह है। यदि किसी भी कार्यस्थल पर महिला के साथ यौन उत्पीड़न या मानसिक प्रताड़ना होती है, तो वह बिना किसी झिझक के इस एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जल्द ही जिले के सभी सरकारी और गैर-सरकारी विभागों में 'अंतरंग परिवाद समितियों' (Internal Complaints Committees) का गठन पूरा किया जाएगा, ताकि हर महिला निर्भय होकर काम कर सके। समिति की वरिष्ठ सदस्य और पत्रकार शशि शर्मा ने इस कानून की बारीकियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' महिलाओं की कार्यक्षमता को सुरक्षित रखने के मकसद से बना है। यह कानून केवल गंभीर मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्यस्थल पर किसी पुरुष अधिकारी या सहकर्मी द्वारा की गई छेड़छाड़, अश्लील इशारे, फब्तियां कसने और यहां तक कि गलत नीयत से घूरने पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान करता है। शशि शर्मा के अनुसार, इस एक्ट के नियमों की जानकारी महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों को भी होना बेहद जरूरी है, ताकि वे अपनी सीमाओं को समझें और महिलाओं के प्रति सम्मानजनक रवैया रखें। समिति की सदस्य और एडवोकेट रश्मि उपाध्याय ने जानकारी दी कि जिलाधिकारी के दिशा-निर्देशन और जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया की देखरेख में जिले में लगातार जागरूकता वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद कार्यस्थल के माहौल को सुरक्षित और खुशनुमा बनाना है, जहां हर कर्मचारी सम्मान के साथ काम कर सके। हरकी पैड़ी पर गंगा पूजन के बाद पॉश समिति के सदस्यों ने गंगा सभा कार्यालय में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) गुरमीत सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की। समिति ने राज्यपाल को जिले में पॉश एक्ट के क्रियान्वयन और भावी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी, जिस पर राज्यपाल ने उनका मार्गदर्शन किया। इस दौरान गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम, महामंत्री तन्मय वशिष्ठ, स्वागत मंत्री सिद्धार्थ चक्रपाणि, अवधेश कौशिक, नीतीश रेहान और बादल अरोड़ा मौजूद रहे। गंगा सभा के पदाधिकारियों ने पॉश समिति की टीम को मां गंगा का प्रसाद और गंगाजली भेंट कर सम्मानित किया।

हरिद्वार में राष्ट्रीय स्वयं सुरक्षा संघ के संगठन विस्तार, तरुण सिरोही बने प्रदेश उपाध्यक्ष

हरिद्वार । राष्ट्रीय स्वयं सुरक्षा संघ द्वारा उत्तराखंड में संगठन को मजबूत करने और इसके व्यापक विस्तार को लेकर हरिद्वार में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश मलिक एवं प्रदेश अध्यक्ष रेशू चैधरी ने उपस्थित कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और संगठन की आगामी कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। कार्यक्रम के दौरान संगठन को और अधिक सक्रिय बनाने के उद्देश्य से तरुण सिरोही को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें हरिद्वार प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई व शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सभी नवनियुक्त पदाधिकारी संगठन की नीतियों, राष्ट्रवादी विचारों और उद्देश्यों को जन-जन तक पहुंचाएं और समाजहित के कार्यों में अपनी सक्रिय व अग्रणी भूमिका निभाएं। मार्गदर्शन सत्र में वक्ताओं ने समावेशिता अभियान पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़ने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्वयं सुरक्षा संघ का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एकता, भाईचारा, सुरक्षा और जनहित की भावना को सुदृढ़ करना है, ताकि समाज के हर वर्ग के साथ मिलकर सकारात्मक कार्य किया जा सके। कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष रेशू चैधरी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश मलिक ने कहा कि समर्पित कार्यकर्ता ही संगठन की असली ताकत होते हैं। उन्होंने सभी से पूरी निष्ठा, अनुशासन और एकजुटता के साथ जनसेवा के कार्यों को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि संगठन हरिद्वार के अंदर गंगा सफाई, गौ रक्षा, नशा मुक्ति हरिद्वार एवं आवश्यकता अनुसार जनहित के कार्य निरंतर करते रहेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित तरुण सिरोही, नरेंद्र पाल, अमित, सचिन,गगन, धर्मेंद्र चैहान, जीवेंद्र सिंह तोमर, दीपक नेहरा, विशाल मलिक, सनोज मलिक, आशुतोष शर्मा, सहित अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन विस्तार, सामाजिक समरसता और समाज सेवा के संकल्प को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का भरोसा दिलाया।

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड 25 रजत जयंती वर्ष

गौरव, विकास और संकल्प का पर्व

देवभूमि रजत उत्सव

विकसित भारत, सशक्त उत्तराखण्ड

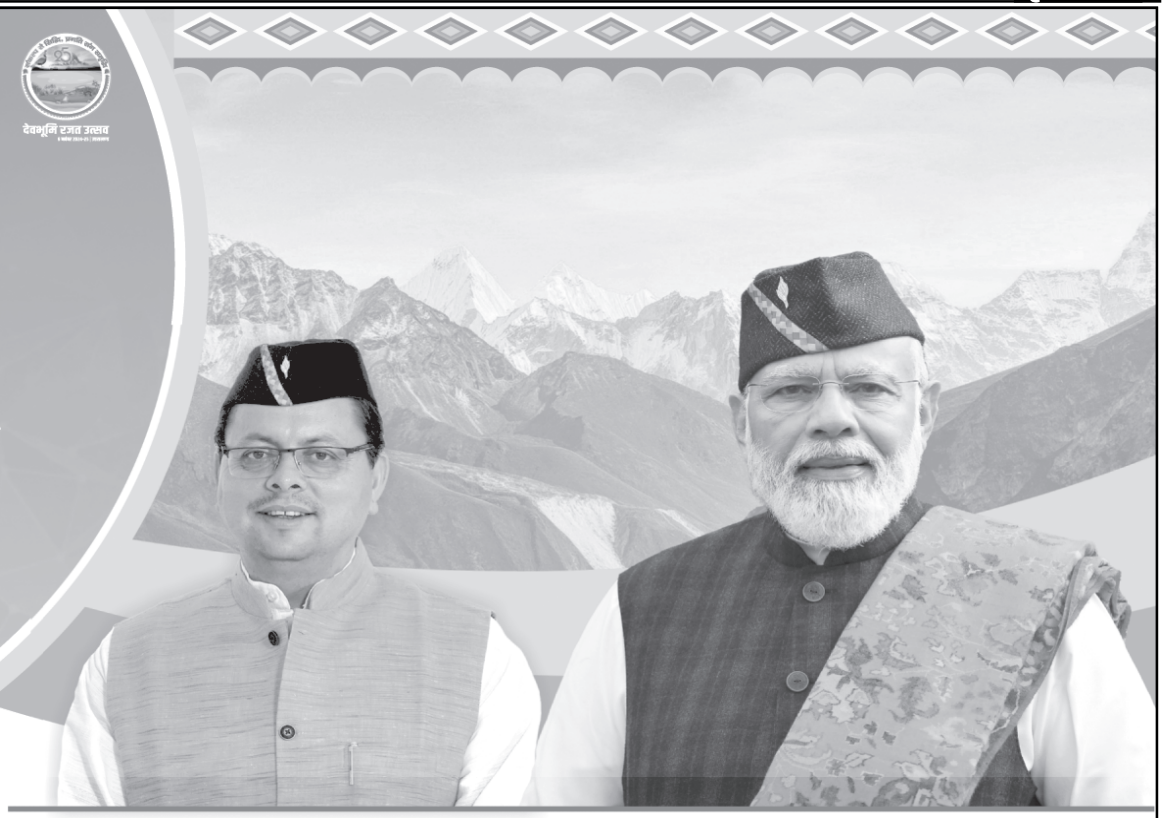

संकल्प से शिखर तक

“ देवभूमि उत्तराखण्ड के लिए यह गौरव का क्षण रहा, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित रजत जयंती समारोह में अपने दूरदर्शी विचारों और प्रेरणादायक सुझावों से विकास की नई दिशा दिखाई। ”

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

“ 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखण्ड, इन दोनों ही स्तंभों को लगातार मजबूत कर रहा है। ये दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा। ”

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

उत्तराखण्ड @2025 से उत्तराखण्ड @2047

संकल्प

प्रधानमंत्री जी के विज़न को साकार करने का

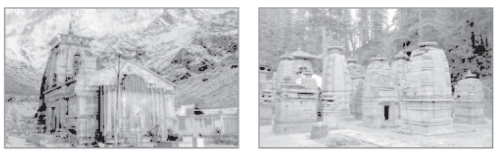

आध्यात्म की वैश्विक राजधानी

- दून विश्वविद्यालय में सेंटर फोर हिन्दू स्टडीज केन्द्र की स्थापना की घोषणा।
- राज्य के 13 जिलों में 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों का हुआ शुभारंभ।
- कुमाऊं में मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के अन्तर्गत पौराणिक मन्दिरों को सर्किट के रूप में जोड़ने का कार्य गतिमान।
- प्रदेश में अगले वर्ष होने वाली श्री नन्दा देवी राजजात यात्रा एवं 2027 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां भी शुरू।

स्थानीय त्योहार

- उत्तराखण्ड अपनी सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और आस्था के अनूठे संगम के लिए जाना जाता है। यहां वर्षभर अनेक धार्मिक, पारंपरिक और लोक मेले आयोजित होते हैं।
- अल्मोड़ा का नंदा देवी मेला, जागेश्वर धाम का श्रावणी मेला, चमोली का गौचर मेला, चंपावत का पूर्णागिरी एवं बग्वाल मेला, पिथौरागढ़ का जौलजीबी मेला, बागेश्वर का उत्तरायणी मेला एवं अन्य प्रमुख मेलों का राज्य सरकार द्वारा हो रहा व्यापक प्रचार-प्रसार।

हार्टिकल्चर हब

- राज्य में किसानों को तीन लाख रुपए तक का बिना ब्याज के दिया जा रहा ऋण।
- किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 'फार्म मशीनरी बैंक' योजना के अंतर्गत 80 फीसदी सब्सिडी।
- राज्य में कलस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस में सब्जी एवं फूलों की खेती के लिए 100 वर्गमीटर आकार के 17648 पॉलीहाउस स्थापना हेतु ₹ 304 करोड़ स्वीकृत, जिसमें कृषकों को दिया जायेगा 70 प्रतिशत अनुदान।

योग एवं वैलनेस

- प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में एक-एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन की होगी स्थापना।
- आयुष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयुष कॉलेजों को 15 लाख तक की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने का प्राविधान।

वेडिंग डेस्टिनेशन

- राज्य सरकार उत्तराखण्ड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में कर रही स्थापित।
- देशभर से बड़ी संख्या में लोग त्रियुगीनारायण मंदिर, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, रामनगर, मुक्तेश्वर ग्वालदम जैसे स्थानों पर विवाह करने आते हैं। इन स्थानों में बुनियादी सुविधाओं का हो विकास एवं शादियों से स्थानीय लोगों को मिले रोजगार, राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है सुनिश्चित।

हस्तशिल्प, आर्गेनिक उत्पाद

- महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत महिला/स्वयं सहायता समूहों को रुपए 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के कराया जा रहा उपलब्ध।
- प्रदेश में अब तक करीब 1 लाख 65 हजार लखपति दीदी बनाई गई।
- उत्तराखण्ड के 15 कृषि उत्पादों को मिला जीआई टैग।

वाईब्रेंट विलेज

- वाईब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अन्तर्गत चयनित 51 गांवों का किया जा रहा सुनियोजित विकास।
- इन गांवों में होमस्टे, स्वरोजगार, खेती स्थानीय उत्पादों एवं सोलर के माध्यम से बिजली उत्पादन को भी दिया जा रहा बढ़ावा।
- राज्य सरकार द्वारा वाइब्रेंट विलेज को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने पर दिया जा रहा जोर।
- पर्यटन केंद्र के बनने से मिलेगा स्थानीय लोगों को रोजगार तथा आर्थिक रूप से होंगें सशक्त।

इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, बारहमासी पर्यटन

- उत्तराखण्ड के जखोल, सूपी, हर्षिल और गुंजी गांवों को भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में पुरस्कृत किया गया।
- एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ऋषिकेश के साथ टनकपुर में रिवर राफ्टिंग की हुई शुरुआत।
- गौरीकुण्ड से केदारनाथ एवं गोविन्दघाट से हेमकुण्ड साहिब तक रोपवे निर्माण कार्य का हुआ शिलान्यास।
- चारधाम शीतकालीन प्रवास स्थान (खरसाली, मुखबा, उखीमठ, पाण्डूकेश्वर) आदि प्रसिद्ध धाम हैं।

हाऊस ऑफ हिमालयाज

- प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विज़न को साकार करने की दिशा में 2023 में हाउस ऑफ हिमालयाज का किया गया शुभारंभ।
- हाउस ऑफ़ हिमालय के अंतर्गत अब तक राज्य की 3,300 ग्रामीण महिलाओं को प्रत्यक्ष एवं 28,000 से अधिक महिलाओं को अप्रत्यक्ष रूप से मिला लाभ।
- 400 से अधिक लोकल क्लस्टर की मैपिंग एवं वर्तमान में 50 से अधिक लोकल क्लस्टर इकाइयों से हो रही सक्रिय खरीदारी।

देवभूमि उत्तराखण्ड में आपका स्वागत है।

प्रधानमंत्री जी के नौ आग्रह

स्थानीय लोगों से: बोली भाषा का संरक्षण, एक पेड़ मां के नाम, स्वच्छ जल, गांव से जुड़ाव, तिबारी वाले घरों को संवारें

पर्यटकों से: सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें, वोकल फॉर लोकल, यातायात के नियम अपनाएं, तीर्थों की मर्यादा का पालन करें

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी | www.uttarainformation.gov.in uttarakhandDIPR DIPR_UK uttarakhand DIPR

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य वन्यजीव बोर्ड और राज्य स्तरीय बाघ संचालन समिति की बैठक

देहरादून । मुख्यमंत्री धामी ने शुक्रवार को राज्य वन्यजीव बोर्ड और राज्य स्तरीय बाघ संचालन समिति की बैठक लेते हुए, प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के साथ ही वन्य जीव आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में आयोजित उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 23वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम, वन्यजीव गलियारों के संरक्षण तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखते हुए सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि वन्यजीव संरक्षण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए भी आधुनिक तकनीक के साथ जनसहभागिता को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और स्थानीय लोगों की आजीविका के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए वन्य जीव आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष के दौरान दूसरे को बचाने के लिए साहसिक प्रदर्शन करने वाले आम लोगों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्य जीवों के हमले में मृत एवं घायल व्यक्ति और उसके परिवार को मानकों के अनुसार तय समय पर मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं में वन्यजीव संरक्षण संबंधी शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में राज्य में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में की गई प्रगति की समीक्षा की गई। बताया गया कि वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान तथा विभिन्न प्रस्तावों पर नियमानुसार स्वीकृतियां प्रदान की जा रही हैं। मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल (त्क्क्ष) गठित करते हुए, कैमरा ट्रैप, ड्रोन, सर्प बचाव किट, सोलर लाइट जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत, निगरानी व्यवस्था तथा वन कर्मियों को आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

बैठक में संरक्षित क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों पर विचार करते हुए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में गैस पाइपलाइन और अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में सड़क, आईटीबीपी अवसंरचना तथा ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी जनहित की परियोजनाओं को आवश्यक शर्तो के अधीन राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को अग्रसारित करने की अनुमति प्रदान की गई। इसके बाद आयोजित राज्य स्तरीय बाघ संचालन समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने

कहा कि उत्तराखण्ड जैव विविधता एवं वन्यजीव संपदा की दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य है। राज्य में बाघ संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों की सहभागिता, आधुनिक तकनीक का उपयोग तथा वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन्यजीव संरक्षण और विकास कार्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए मानव-वन्यजीव संघर्ष को न्यूनतम करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वन्यजीव कॉरिडोरों का संरक्षण, कैमरा ट्रैप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित निगरानी तथा वैज्ञानिक प्रबंधन को और मजबूत किया जाए। उन्होंने वन्यजीवों के प्राकृतिक जल स्रोतों एवं चारागाहों के विकास, वनाग्नि प्रबंधन तथा संवेदनशील क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली को विस्तार देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार कुंभ के दौरान मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए क्यूआरटी टीम की तैनाती की जाए।

बैठक में कॉर्बेट एवं राजाजी टाइगर रिजर्व के लिए टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन, पर्यावरण अनुकूल सफारी वाहनों को बढ़ावा देने, संरक्षित क्षेत्रों में कार्यरत फील्ड स्टाफ के लिए विशेष प्रोत्साहन तथा वन्यजीव अपराधों की प्रभावी जांच के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई।

बैठक में वन मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक दीवान सिंह बिष्ट, उपाध्यक्ष उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद गीताराम गौड़, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक हॉफ कपिल लाल, एडीजी ए.पी. अंशुमन, सचिव सी रविशंकर , प्रमुख वन संरक्षक नीना ग्रेवाल एवं वन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

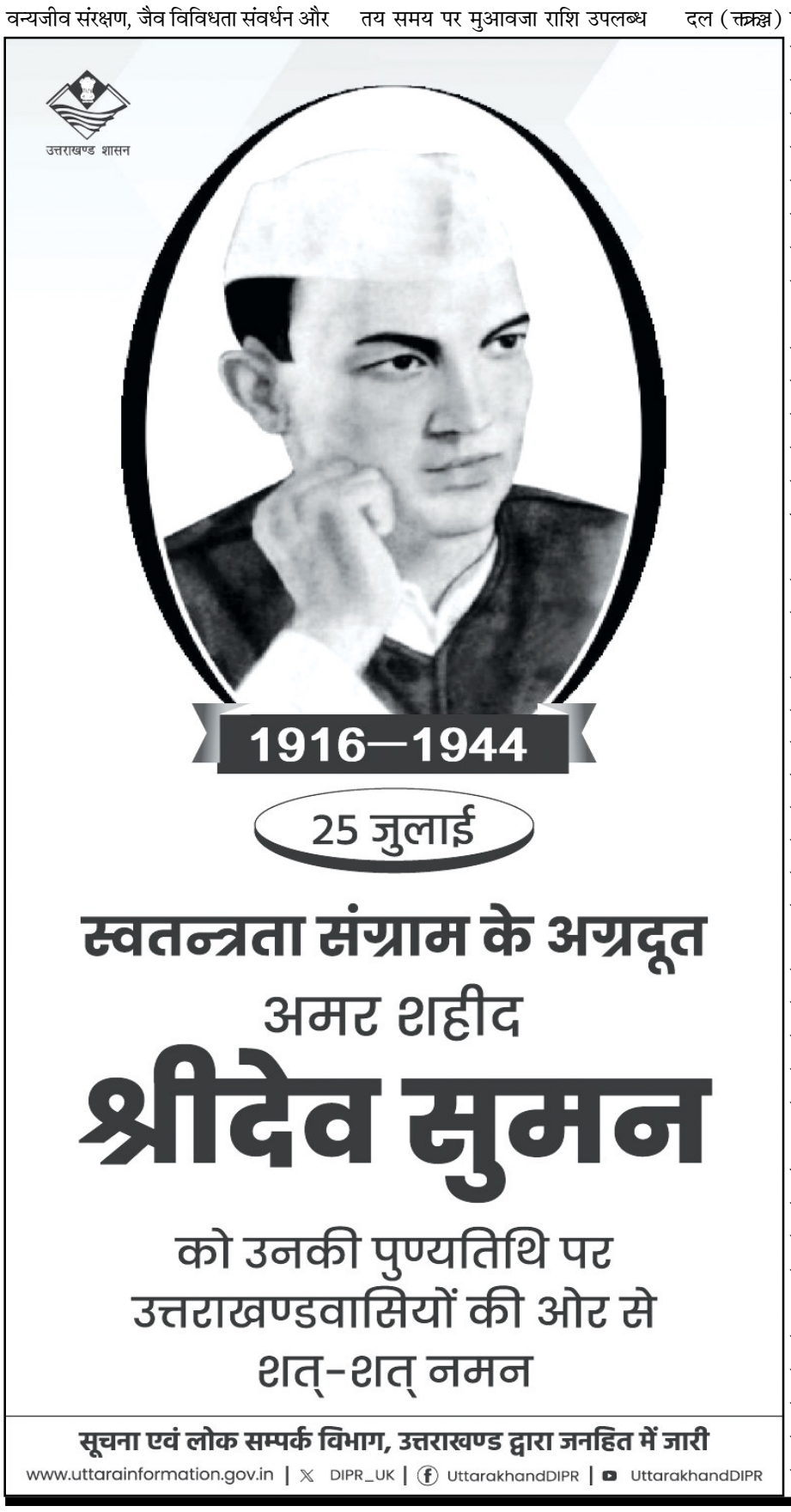

एक पेड़ मां के नाम' अभियान का गुरुकुल कांगड़ी से शुभारंभ

हरिद्वार । भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ हरिद्वार ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की शुरुआत गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने पौधरोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है और इस दिशा में चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रयास सराहनीय है। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉ. विकास दीक्षित के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम की व्यवस्था गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के आईक्यूएसी विभाग के निदेशक डॉ. पंकज मदान की देखरेख में की गई। भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा विशिष्ट अतिथि रहे, जबकि प्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह-संयोजक डॉ. संदीप गौर ने कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया।भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने प्रकोष्ठ की गतिविधियों को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया।संचालन एवं समन्वय डॉ. गौरव मनोचा और डॉ. प्रणव यादव ने किया। इस अवसर पर भाजपा जिला प्रकोष्ठ संयोजक प्रमोद शर्मा, मंडल अध्यक्ष विपिन शर्मा, पार्षद नागेंद्र राणा, डॉ. विपिन शर्मा, डॉ. निशांत कुमार, डॉ. चिरंजीव बनर्जी, डॉ. मिथिलेश पांडे, डॉ. रत्नेश कुमार, डॉ. कपिल पांडे, डॉ. नवनीत, डॉ. संदीप, अमित, अरविंद, ललित नेगी, प्रवीण, हर्ष आदि मौजूद रहे।

बैग छीन कर भागे तीन आरोपियों को हिरासत में लिया

हरिद्वार । कांवड़ यात्रा 2026 के दौरान मंगलवार को यात्रियों का बैग छीन कर भाग रहे तीन आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तलाशी लेने पर आरोपियों के कब्जे से छीना गया बैग और उसमें रखे चार मोबाइल फोन बरामद हुए है। मंगलवार को गुजरावाला चौक के पास से कांवड़ ड्यूटी के दौरान पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लिया। आरोप है कि तीनों आरोपी यात्रियों का पीछा कर रहे थे। मौका मिलने पर आरोपियों ने यात्रियों का बैग छीन लिया। बैग छीन कर आरोपी भागने लगे। लेकिन कांवड़ मेले में भारी भीड़ के बीच पुलिस की त्वरित कार्रवाई से तीनों आरोपी पकड़े गए। बैग सुरक्षित बरामद होने पर यात्रियों ने राहत की सांस ली। पुलिस ने तीनों युवकों को बरामद बैग सहित सहित नगर कोतवाली पहुंचाया। बरामद बैग और मोबाइल सुरक्षित जमा करा दिए गए हैं। एसएचओ कुंदन सिंह राणा ने बताया कि तीन आरोपी लक्की, गौतम और जोनी निवासी जगजीतपुर कनखल को हिरासत में लिया गया है। तीनों आरोपी नशे के आदी हैं।

व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित

हरिद्वार । कांवड़ मेले को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से हरकी पौड़ी चौकी में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ मंगलवार की समन्वय बैठक आयोजित हुई। बैठक में कांवड़ मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन, आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी और पुलिस व्यापारी समन्वय सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। मंगलवार को सुपर जोनल अधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद की अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में एएसपी ने व्यापारियों से मेले के दौरान प्रशासन के जारी दिशा निर्देशों का पालन करने और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की। बैठक में व्यापारियों ने पुलिस को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में जोन प्रथम के जोनल अधिकारी, सहायक जोनल अधिकारी, सेक्टर प्रभारी और हरकी पैड़ी चौकी प्रभारी मौजूद रहे।

उत्तराखण्ड शासन

देवभूमि दशत उत्सव

उत्तरोत्तर विकास पथ पर अग्रसर

देवभूमि उत्तराखण्ड

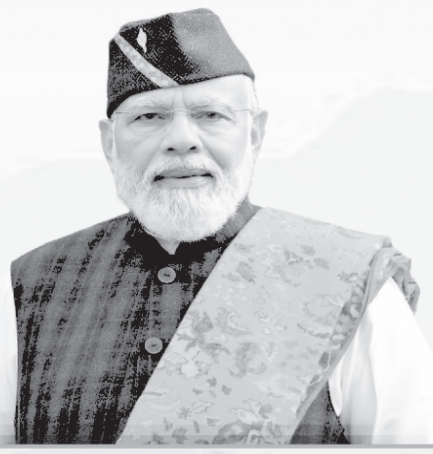

"21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखण्ड इन दोनों ही स्तंभों को लगातार मजबूत कर रहा है। ये दशक उत्तराखण्ड का दशक है।"

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

"प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड सर्वांगीण विकास की नई मिसाल बन रहा है। स्थानीय उत्पाद, बेहतर कनेक्टिविटी, उद्योग एवं निवेश तथा हर मौसम पर्यटन सहित देवभूमि अपनी अलौकिक विरासत को संजोते हुए विकास के नए आयाम छू रही है।"

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

विकसित भारत सशक्त उत्तराखण्ड

विरासत भी, विकास भी

इंफ्रास्ट्रक्चर एवं कनेक्टिविटी

- केदारनाथ–हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना
- दिल्ली–देहरादून एलिवेटेड रोड निर्माण
- ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रगति पर
- टनकपुर–बागेश्वर रेल सर्वे स्वीकृत
- सौंग व जमरानी बांध परियोजना
- पर्वतीय जिलों में हेली सेवा विस्तार

अर्थव्यवस्था, निवेश एवं उद्योग

- ₹3.56 लाख करोड़ निवेश समझौते
- ₹1 लाख करोड़+ ग्राउंडिंग
- अर्थव्यवस्था 26 गुना वृद्धि
- ₹1.11 लाख करोड़+ वार्षिक बजट
- खुरपिया में स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप
- हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड

हरित ऊर्जा एवं ग्रामीण विकास

- 1 गीगावाट+ सौर ऊर्जा क्षमता
- 42,000+ सोलर रूफटॉप
- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (सीमांत गांव विकास)
- महक क्रांति व मिलेट्स मिशन

संस्कृति एवं विरासत का संरक्षण

- केदारनाथ–बदरीनाथ मास्टर प्लान
- मानसखण्ड मंदिर माला मिशन
- शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ
- संस्कृत ग्राम पहल
- गीता अध्ययन पाठ्यक्रम में शामिल
- दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र
- स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन (गढ़वाल–कुमाऊं)

सुशासन

- 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान
- 30,000+ युवाओं को सरकारी नौकरी
- 950+ सेवाएं ऑनलाइन (अपुणि सरकार पोर्टल)
- 12,000 एकड़ अतिक्रमण मुक्त
- पेंशन योजनाओं में वृद्धि एवं मासिक भुगतान

बड़े निर्णय

- समान नागरिक संहिता
- सशक्त भू-कानून
- सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून
- नकल विरोधी कानून
- अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण

संकल्प से शिखर तक

नेशनल लेवल रैंकिंग व प्रोत्साहन

- निर्यात तैयारी सूचकांक में प्रथम (छोटे राज्य)
- एसडीजी इंडेक्स में शीर्ष स्थान
- स्टार्टअप रैंकिंग में 'लीडर'
- खनन सुधारों में देश में दूसरा स्थान
- शहरी सुधारों हेतु ₹264.5 करोड़ प्रोत्साहन

30 से अधिक नीतियां

नीतिगत सुधार

- औद्योगिक नीति, पर्यटन एवं योग नीति
- नई फिल्म नीति (50% तक सब्सिडी)
- मिलेट्स नीति, कीवी नीति (70% अनुदान)
- ड्रैगन फ्रूट प्रोत्साहन योजना
- महक क्रांति 2026-36
- महिला स्वरोजगार एवं लखपति दीदी योजना आदि

प्रधानमंत्री जी के नौ आग्रह

स्थानीय लोगों से: बोली-भाषा का संरक्षण, एक पेड़ मां के नाम, स्वच्छ जल, गांव से जुड़ाव, तिबारी वाले घरों को संवारें

पर्यटकों से: प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें, वोकल फॉर लोकल, यातायात के नियम अपनाएं, तीर्थों की मर्यादा का पालन करें।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी

www.uttarainformation.gov.in | DIPR_UK | UttarakhandDIPR | UttarakhandDIPR

उत्तराखण्ड शासन | देवभूमि रजत उत्सव | उत्तराखण्ड 25 रजत जयंती वर्ष
गौरव, विकास और संकल्प का पर्व

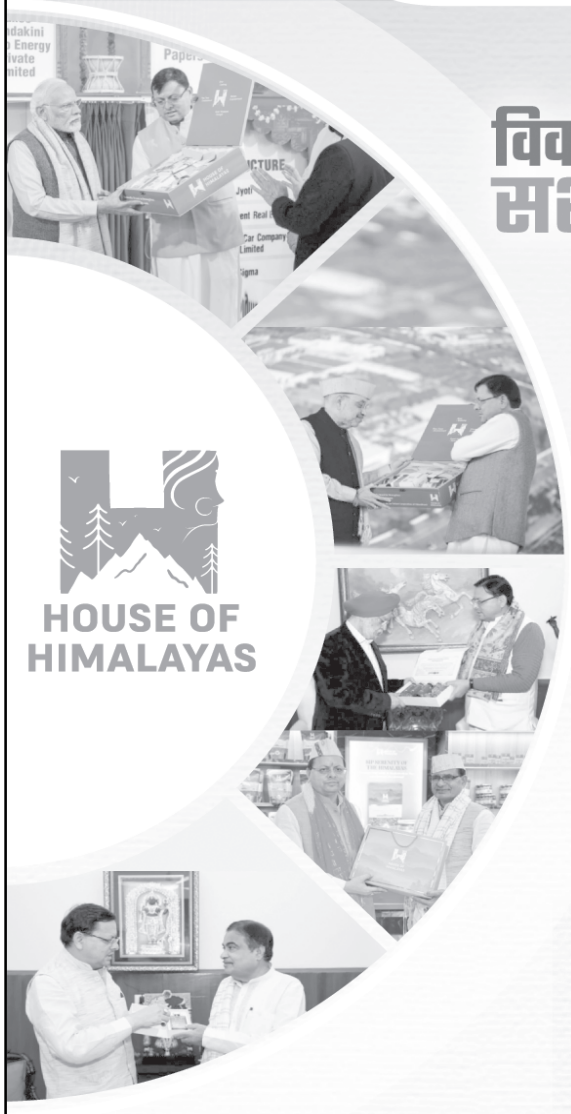

विकसित भारत सशक्त उत्तराखण्ड

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हम अपने राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अपार संभावनाओं का लाभ उठाते हुए समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उत्तराखण्ड को प्रगति का एक ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं, जहां व्यक्ति राज्य की समृद्धि व कल्याण में अपना अपार योगदान दे सकता है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

हमें स्वदेशी को अपना स्वाभिमान बनाना है। इसे अपनाना केवल सामान खरीदने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे गर्व के साथ बढ़ावा देना हर नागरिक का कर्तव्य है। इससे स्थानीय उद्योग सशक्त होंगे, रोजगार बढ़ेंगे और देश की आर्थिक तरक्की में मदद मिलेगी। त्योहारों के अवसर पर देश के प्रत्येक नागरिक स्वदेशी सामान खरीदें। यह छोटा कदम देश की बड़ी प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और इसे अपनाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

उत्तराखण्ड के जैविक उत्पाद
अब दुनिया की पहली पसंद

हाउस ऑफ हिमालयाज से मिला स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार पहाड़ी क्षेत्रों के उन्नत उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। साथ ही, उनके विपणन के लिए कई पहल भी शुरु की गई है। 'हाउस ऑफ हिमालयाज' की शुरुआत इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अंतर्गत उत्तराखण्ड के उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को देश और दुनिया के बाजारों के अनुरुप तैयार किया गया है। ये उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्र के उत्पादों का एक प्रमुख ब्रांड बनकर उभरे हैं।

उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अन्य करोड़ों की परियोजनाओं के साथ 'हाउस ऑफ हिमालयाज' नामक 'अंब्रेला ब्रांड' का शुभारंभ किया था। जिसके तहत, अब समूहों द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पाद 'हाउस ऑफ हिमालयाज' के नाम से बाजार में उपलब्ध हैं। इन उत्पादों की क्वालिटी एवं पैकिंग आदि पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को विदेशी बाजारों तक ले जाने का एक अभिनव प्रयास है। देवभूमि उत्तराखण्ड के उत्पाद स्वाद और सेहत जैसे कई प्राकृतिक गुणों से भरपूर हैं। कुछ समय पहले तक हिमालय की गोद से निकलने वाले ये उत्पाद हिमाद्री, हिलांस और ग्राम्य-श्री जैसे नामों से बाजार में जाने जाते थे। लेकिन, अब ये दमदार उत्पाद 'हाउस ऑफ हिमालयाज' के नाम से जाने-पहचाने जाते हैं। यानी उत्तराखण्ड के महिला समूहों द्वारा तैयार अलग-अलग उत्पाद अब 'हाउस ऑफ हिमालयाज' के नाम से दुनियाभर में अपना कमाल दिखा रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालयाज, उत्तराखण्ड के उत्पादों को वोकल फॉर लोकल से लोकल टू ग्लोबल बनने में मदद करेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार पहाड़ी क्षेत्रों के उन्नत उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। साथ ही, उनके विपणन के लिए कई पहल भी शुरू की गई है। 'हाउस ऑफ हिमालयाज' की शुरूआत इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अंतर्गत उत्तराखण्ड के उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को देश और दुनिया के बाजारों के अनुरूप तैयार किया गया है। ये उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्र के उत्पादों का एक प्रमुख ब्रांड बनकर उभरे हैं।

बेहतर गुणवत्ता : हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद बेहद खास हैं, जो अपनी बेजोड़ गुणवत्ता और बेहतर कारीगरी के लिए जाने जाते हैं। यह बातें उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादन होने वाले दूसरे उत्पादों से विशिष्ट बनाती हैं।

हाउस ऑफ हिमालयाज
इसलिए है खास

प्रामाणिकता का आश्वासन: पारंपरिक तरीकों और प्रामाणिक अनुभवों को केंद्र में रखते हुए इस पहल के अंतर्गत बनाए जा रहे उत्पाद उच्च गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरने के बाद ही ग्राहकों तक भेजे जाते हैं। इन उत्पादों की उच्च गुणवत्ता की पुष्टि करने के लिए इन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाता है।

सामुदायिक प्रतिबद्धता: हाउस ऑफ हिमालयाज को चुनने का मतलब है, सार्थक सामाजिक पहलों के माध्यम से स्थानीय समुदायों का समर्थन करना। इसके हर उत्पाद की खरीद के साथ आप सामाजिक रूप से योगदान दे सकते हैं।

ओपन सोर्सिंग: इस पहल के अंतर्गत सामग्री और उत्पादन प्रक्रियाओं को चुनते समय पूर्ण पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि उपभोक्ता का भरोसा बनाए रखा जा सके।

नैतिकता को प्राथमिकता: स्थायी सोर्सिंग और बेहतर उत्पादन के तरीके अपनाने के साथ यह ब्रांड उन तरीकों को अपनाता है, जिसकी नैतिक तौर पर सराहना की जाती है।

बेहतर ब्रांड अनुभव: उत्पाद की पूरी जानकारी, छोटी से छोटी बारीकी का ध्यान और बेहतर उत्पाद को शामिल करके यह ब्रांड ग्राहकों को एक बेहतर अनुभव प्रदान करता है, जो हर उपभोक्ता के लिए यादगार अनुभव साबित होता है।

ODOP ONE DISTRICT TWO PRODUCTS UTTARAKHAND
एक जिला-दो उत्पाद योजना के साथ दुनिया को लुभा रहे उत्तराखण्ड के उत्पाद

जिला	उत्पाद-1	उत्पाद-2
अल्मोड़ा	बाल मिठाई	ट्वीड
बागेश्वर	ताम्र शिल्प उत्पाद	कीवी के उत्पाद
चमोली	गुलाब जल	हथकरघा के उत्पाद
हरिद्वार	शहद	जैगरी
चम्पावत	शहद	लोहे के उत्पाद
देहरादून	बेकरी उत्पाद	मशरूम के उत्पाद
रूद्रप्रयाग	चौलाई के उत्पाद	मंदिर अनुकृति हस्तशिल्प
नैनीताल	ऐपण हस्तशिल्प	फल प्रसंस्करण
पौड़ी	हर्बल मेडिसिन	लकड़ी शिल्प
ऊधम सिंह नगर	मैंथा ऑयल	मूंज ग्रास उत्पाद
उत्तरकाशी	सेब के उत्पाद	लाल चावल
पिथौरागढ़	मुन्स्यारी राजमा	ऊनी कालीन
टिहरी	पनीर	टिहरी नथ

लोकल से ग्लोबल की ओर उत्तराखण्ड के शिल्प और जैविक उत्पाद

पर्यटक अपने यात्रा व्यय का 5%
स्थानीय उत्पादों पर खर्च करें: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वोकल फॉर लोकल की बात कही है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' की शुरूआत की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार ने इस योजना को 'वन डिस्ट्रिक्ट-टू प्रोडक्ट' के रूप में आगे बढ़ाया है। बदरीनाथ धाम के निकट माणा में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि कहीं भी घूमने जाएं तो अपने यात्रा व्यय का 5 प्रतिशत स्थानीय उत्पादों पर खर्च करें। इससे स्थानीय आर्थिकी में जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेगा। किसी भी क्षेत्र की पहचान उनकी भाषा-बोली एवं स्थानीय उत्पादों से होती है, इनको बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किये जाने चाहिए।

देवभूमि के पारंपरिक उत्पाद विशिष्ट जीआई टैग से सम्मानित

उत्तराखण्ड का भोटिया दन

यह उत्तराखण्ड में भोटिया समुदाय द्वारा बनाया गया एक पारंपरिक हाथ से बुना हुआ कालीन है। ये कालीन अपनी गर्माहट, टिकाऊपन और जटिल डिजाइन के लिए जाने जाते हैं।

उत्तराखण्ड थुलमा

थुलमा कंबल उत्तराखण्ड में भोटिया समुदाय द्वारा भेड़ या याक के ऊन का उपयोग करके हाथ से बुना जाता है। ये कंबल अपनी गर्माहट, टिकाऊपन के लिए जाने जाते हैं।

उत्तराखण्ड लिखाई (लकड़ी की नक्काशी)

उत्तराखण्ड अपनी बेहतरीन लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, कुशल कारीगर लकड़ी को जटिल तरीके से तराश कर सुंदर डिजाइन और रूपांकन बनाते हैं।

नैनीताल मोमबत्तियां (मोमबत्ती)

उत्तराखण्ड अपनी कलात्मक मोमबत्तियों के लिए जाना जाता है, ये मोमबत्तियां अक्सर क्षेत्र के सांस्कृतिक रूपांकनों और प्रतीकों को दर्शाती हैं।

कुमाऊं की रंगवाली पिछौड़ा

रंगवाली पिछौड़ा एक पारंपरिक शिल्प है, जिसमें रंगीन हाथ से छपी/हाथ से बुनी हुई सूती/रेशमी/ऊनी शॉलें बनाई जाती हैं। डिजाइन और पैटर्न कुमाऊं क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं।

उत्तराखण्ड ऐपण

ऐपण एक पारंपरिक लोककला है, जिसे चावल के पेस्ट या चाक का उपयोग करके तैयार किया जाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान यह लोककला फर्श, दीवारों या आंगनों पर देखा जाता है।

जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) शिल्प उत्पाद

भौगोलिक संकेत (जीआई) उन उत्पादों पर प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है, जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है तथा उनमें उस उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है। दूसरे शब्दों में, यह एक प्रमाणीकरण है, जो किसी उत्पाद को किसी विशेष क्षेत्र से उत्पन्न होने की पहचान कराता है, जहां उत्पाद की दी गई गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य विशेषता अनिवार्य रूप से उसके भौगोलिक उत्पत्ति के कारण होती है।

उत्तराखण्ड के निम्नलिखित शिल्प उत्पादों को भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है

उत्तराखण्ड बिछुआ बूटी

बिछुआ फाइबर का उपयोग कपड़े, बैग और रस्सियों सहित कई उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है। इसके फाइबर को इसकी मजबूती और पर्यावरण-मित्रता के लिए महत्व दिया जाता है।

उत्तराखण्ड रिंगाल शिल्प

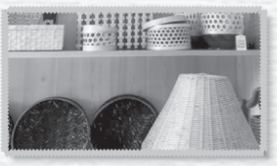

रिंगाल उत्पाद एक प्रकार की स्थानीय घास से तैयार किए जाते हैं। कारीगर इसकी मजबूती और लचीलेपन के कारण चटाई, टोकरी और रस्सी जैसी वस्तुएं बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं।

चमोली लकड़ी का रावण मुखौटा

रावण मुखौटे लकड़ी से उकेरे जाते हैं और पारंपरिक लोक नृत्यों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों में उपयोग किए जाते हैं।

उत्तराखण्ड तमता उत्पाद

उत्तराखण्ड के कारीगर तांबे का उपयोग करके बर्तन, सजावटी सामान और धार्मिक कलाकृतियां जैसी विभिन्न वस्तुएं बनाते हैं।

'भ्रमण से भ्रम मिटते हैं, सीमांत गांव देश के प्रहरी भी हैं और पहला पड़ाव भी': प्रधानमंत्री मोदी

देहरादून । देश की सीमाओं पर बसे गांवों को विकास की मुख्यधारा में लाने और उनकी सामरिक व सांस्कृतिक महत्ता से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के उद्देश्य से संचालित 'विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-2026' के तहत एक ऐतिहासिक संवाद संपन्न हुआ। रविवार को आयोजित विशेष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 सीमावर्ती गांवों का भ्रमण कर लौटे 400 से अधिक उत्साही युवाओं से सीधा संवाद किया और उनके जमीनी अनुभवों को आत्मीयता से सुना। 'माइ भारत' प्लेटफॉर्म के जरिए आयोजित इस राष्ट्रव्यापी पहल में 3 लाख से अधिक युवाओं ने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें से देश भर के 403 उत्कृष्ट युवाओं का चयन हुआ। इस यात्रा में उत्तराखंड के 15 और अकेले देहरादून जिले के 06 युवाओं-शिवांग रमोला, नेहा रेवंकर, पलक पांथरी, आकांक्षा बिष्ट, संदीप नेगी एवं वरदान' ने सीमांत जीवन की जीवंत झलक को आत्मसात किया।

'अंतिम नहीं, देश का पहला गांव हैं सीमावर्ती क्षेत्र'

संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रेखांकित किया कि सरकार की सोच में अब बदलाव आ चुका है। सीमावर्ती गांव देश के अंतिम छोर नहीं, बल्कि भारत के 'पहले गांव' हैं।प्रधानमंत्री ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा, 'भ्रमण से ही मन के भ्रम मिटते हैं। हमारे सीमांत गांव भले ही दूरस्थ हों, लेकिन वहां रचने-बसने वाली देशभक्ति, अनूठी संस्कृति और समृद्ध परंपराएं पूरे देश को 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के सूत्र में पिरोती हैं। इन क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों के बावजूद राष्ट्रनिष्ठा का जो जज्बा है, वह हर भारतवासी के लिए वंदनीय है।' उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने अनुभवों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और सीमांत पर्यटन को बढ़ावा दें।

30 दिनों का अविस्मरणीय सफर, विकास और संवेदना का संगम

विगत 3 से 30 जून तक चले दो चरणों के इस विस्तृत भ्रमण के दौरान युवाओं ने सीमांत गांवों में पहुंच रही मूलभूत सुविधाओं 'पक्की सड़कें, निर्बाध बिजली-पानी, सोलर लाइट, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल बैंकिंग' की जमीनी हकीकत को करीब से देखा।

युवाओं ने प्रधानमंत्री के समक्ष अपने संस्मरण साझा करते हुए कहा कि सीमांत क्षेत्र के निवासियों का आतिथ्य और देशभक्ति का भाव मन को छू लेने वाला था। यह यात्रा महज एक शैक्षणिक भ्रमण नहीं, बल्कि जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का एक भावुक और संवेदनात्मक अनुभव साबित हुई।

एनआईसी देहरादून में दिखा युवाओं का उत्साह

इस वर्चुअल संवाद के दौरान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र देहरादून परिसर में उत्साह का माहौल रहा। कार्यक्रम में परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, राज्य निदेशक राहुल डबराल, उप निदेशक मोनिका नांदल, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अंकुश पांडेय सहित माइ भारत संगठन से जुड़े अनेक युवा और अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने प्रधानमंत्री की इस दूरदर्शी पहल की सराहना करते हुए इसे युवाओं में राष्ट्रीय चेतना जगाने वाला अभूतपूर्व कदम बताया।

सफलता का आधार केवल अंक नहीं, चरित्र और संस्कार भी जरूरी : डीजी सूचना बंशीधर तिवारी

देहरादून । डीजी सूचना एवं मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे केवल शैक्षणिक उपलब्धियों तक सीमित न रहें, बल्कि ज्ञान, चरित्र, नैतिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व को अपने जीवन का आधार बनाकर समग्र सफलता की ओर अग्रसर हों। वह एसबीएस यूनिवर्सिटी और द टाइम्स ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में देहरादून के नगर निगम टाउन हॉल ऑडिटोरियम में आयोजित 'टाइम्स अचीवर्स 2026' समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि निरंतर प्रयास, सीखने की प्रवृत्ति और मजबूत जीवन मूल्यों का परिणाम होती है। उनके अनुसार शैक्षणिक उत्कृष्टता सफलता का केवल एक पहलू है, जबकि सफल करियर, व्यक्तिगत खुशहाली और मजबूत पारिवारिक मूल्य मिलकर जीवन को वास्तविक अर्थों में सफल बनाते हैं।

तिवारी ने विद्यार्थियों को परीक्षा के अंकों और डिग्रियों से आगे बढ़कर ईमानदारी, अनुशासन, धैर्य, संवेदनशीलता और उद्देश्यपूर्ण जीवन जैसे गुण अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि करियर में सफलता अवसर देती है, लेकिन वास्तविक संतुष्टि परिवार के मूल्यों का सम्मान करने और समाज के प्रति सकारात्मक योगदान देने से मिलती है। उन्होंने कहा कि तेजी से विकसित हो रहे भारत को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है, जो पेशेवर उत्कृष्टता के साथ नैतिक नेतृत्व, नवाचार और जिम्मेदार नागरिकता का परिचय दें। उन्होंने विद्यार्थियों से सफलता के साथ विनम्रता और कृतज्ञता बनाए रखने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर बंशीधर तिवारी ने एसबीएस यूनिवर्सिटी और द टाइम्स ऑफ इंडिया की सराहना करते हुए कहा कि 'टाइम्स अचीवर्स 2026' जैसे आयोजन मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने के साथ उन्हें बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। समारोह में विभिन्न विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले संस्थानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षाविदों, संस्थान प्रमुखों, अभिभावकों और विद्यार्थियों की बड़ी संख्या मौजूद रही।

देहरादून में 232 गरीब परिवारों का सपना सच: एमडीडीए ने लॉटरी से बांटे ईडब्ल्यूएस फ्लैट, दिव्यांगों को भूतल

देहरादून । राजधानी के आईएसबीटी स्थित सिटी जंक्शन मॉल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 232 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के परिवारों का अपने पक्के घर का इंतजार खत्म हो गया। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने धौलास आवासीय योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पंजीकृत लाभार्थियों को पारदर्शी डिजिटल लॉटरी प्रक्रिया के जरिये भवन संख्या आवंटित कीं। कंप्यूटरीकृत प्रणाली से संपन्न इस लॉटरी में अधिकारियों और आवेदकों की मौजूदगी के बीच एक-एक कर फ्लैट नंबर निकाले गए। एमडीडीए प्रशासन ने मानवीय संवेदनाओं का ख्याल रखते हुए विशेष प्राथमिकता दी। इसके तहत 4 दिव्यांगों और 2 वरिष्ठ नागरिकों को सीढ़ियां चढ़ने की असुविधा से बचाने के लिए सीधे भूतल पर ही फ्लैट आवंटित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार 'हर पात्र परिवार को अपना घर' देने के संकल्प के साथ काम कर रही है। जरूरतमंद वर्ग को सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन देना ही सरकारी प्राथमिकताओं के केंद्र में है। आने वाले दिनों में ऐसी और भी जनहितकारी योजनाएं धरातल पर उतारी जाएंगी ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सिर पर पक्की छत से वंचित न रहे। धौलास में विकसित की जा रही यह परियोजना आधुनिक नागरिक सुविधाओं और सुनियोजित निर्माण तकनीक से लैस है। पूर्व में निर्माणदायी एजेंसी ब्रिज एंड रूफ को गति बढ़ाने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद प्रोजेक्ट के बुनियादी ढांचे और ईडब्ल्यूएस ब्लॉकों का काम तेजी से निपटाया गया। अब डिजिटल आवंटन के साथ ही लाभार्थियों को जल्द कब्जा सौंपने की प्रशासनिक तैयारी चल रही है।

कार्यक्रम में एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने स्पष्ट किया कि आवंटन की पूरी प्रक्रिया नियमों के कड़े दायरे में

डिजिटल माध्यम से की गई है। किसी भी तरह के मानवीय हस्तक्षेप से परे यह प्रणाली पूरी तरह निष्पक्ष रही। उपस्थित लोगों ने तुरंत स्क्रीन पर अपनी अलॉटमेंट लिस्ट देखी, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मुहर लगी। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने जोर देकर कहा कि प्राधिकरण का ध्यान सिर्फ कंक्रीट के ढांचे खड़े करने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण परिवेश तैयार करना है। पूरी पारदर्शी लॉटरी के दौरान आवेदकों की आंखों में खुशी के आंसू और अपने घर की चाबी मिलने का संतोष साफ नजर आया। राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना को गरीब कल्याण की मजबूत रीढ़ मानकर चल रही है। धौलास आवासीय योजना के जरिए 232 परिवारों को मिला नया ठिकाना इसी दूरगामी नीति और जन-कल्याणकारी सोच का परिणाम है।

स्वामी,मुद्रक व प्रकाशक अवनीश कुमार द्वारा भगवती प्रिंटर्स,इण्डस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार से छपवाकर ग्रा. बसवाखेड़ी पो. मंगलौर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड़) से प्रकाशित किया।
सम्पादकः अवनीश कुमार, मो० 9410553400
ई-मेल: liveskgnews@gmail.com
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र हरिद्वार न्यायालय में ही होगा)
सभी लेखों में सम्पादक की सहमति जरूरी नही है।